



कल की आशा में सोने वाला व्यक्ति
कभी जाग नहीं सकता।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 97 ● वर्ष : 11 ● रायपुर, मंगलवार 03 अक्टूबर 2023 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन



छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को समर्पित
मोदी सरकार

₹ 26 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का
राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास



राष्ट्र को समर्पण

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट

- बस्तर के स्थानीय समुदाय का सपना हुआ पूरा
- हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार
- भारत और दुनिया के स्टील मानचित्र पर स्थापित हुआ बस्तर

जगदलपुर-दंतेवाड़ा रेल लाइन का दोहरीकरण

- बेहतर यात्री और माल परिवहन कनेक्टिविटी
- देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान

अंतागढ़ - ताड़ोकी नई रेल लाइन

- छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीधा रेल संपर्क
- आदिवासी बहुल क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का नया युग

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (पुराना रा. रा. - 78) के कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखण्ड सीमा खंड का
2 लेन मय पेंड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं उत्थान

- छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के बीच यात्री और माल की निर्बाध आवाजाही
- जशपुर, सरगुजा एवं आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास

शिलान्यास

बोरीडांड-सूरजपुर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना

- छत्तीसगढ़ को देश के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग से जोड़ने का सुविधाजनक मार्ग
- स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन का उत्थान

- स्थानीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा
- रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं

शुभारंभ

ताड़ोकी-रायपुर DEMU ट्रेन सेवा

- अंतागढ़ से ताड़ोकी तक ट्रेन सेवा का विस्तार
- विद्यार्थियों, व्यापारियों और व्यवसायियों को लाभ

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री
के कर कमलों द्वारा

श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री दीपक बैज
सांसद

श्री नारायण चंदेल

विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

श्री अरुण साव
सांसद

दिनांक: 3 अक्टूबर, 2023 | समय: 1100 बजे | स्थान: लालबाग मैदान, जगदलपुर



कार्यक्रम का सीधा प्रसारण DD NEWS पर देखें

भारतीय रेल

f RailMinIndia पर हमें फॉलो करें

संपादकीय

अमेरिका खेलेगा कश्मीर कार्ड?

विचार

यहीं सोच समर्थ्या है

प्रश्न है कि उन 19 थाना क्षेत्रों को क्यों छोड़ दिया गया ? एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लगभग पांच महीनों में मणिपुर में हुई हिंसा की तमाम घटनाओं के बीच तकरीबन 80 फीसदी वारदात उन्हीं थाना क्षेत्रों में हुई हैं। मणिपुर में बेकाबू हालात के बीच 19 थाना क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी वहां सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून लागू हो गया है। प्रश्न है कि उन 19 थाना क्षेत्रों को क्यों छोड़ा दिया गया ? एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लगभग पांच महीनों में मणिपुर में हुई हिंसा की तमाम घटनाओं के बीच तकरीबन 80 फीसदी वारदात उन्हीं थाना क्षेत्रों में हुई हैं। मगर इन क्षेत्रों को इसलिए बख्खा गया, क्योंकि वहां बहुसंख्यक मैत्री आबादी रहती है। जबकि जिन क्षेत्रों में अपसपा लागू किया गया है, वे पहाड़ी इलाके हैं, जहां ज्यादातर कुकी आबादी ज्यादा है। इस संदर्भ में यह पहलू रेखांकित करने का है कि हिंसा की इस लंबी अवधि में राज्य सरकार- खासकर मुख्यमंत्री बोरेन सिंह पर मैत्री समुदाय की तरफ से काम करने के आरोप लगते रहे हैं। राज्य प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा है, यह बात अपने ढंग से देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है। इसके बावजूद उनकी पीठ पर केंद्र सरकार का हाथ बना हुआ है। सरकार में कुकी समुदाय को निशाने पर रखने का नजरिया कितना हावी है, इसकी स्पष्ट मिसाल देखनी हो, तो न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए बयान पर गौर करना चाहिए। जयशंकर ने म्यांमार से आए शरणार्थियों को हिंसा का प्रमुख कारण बताया। इसके तरह मैत्री समुदाय की खुद को जनजाति घोषित कराने की मांग और उससे उपर्युक्त तानाव जैसी बुनियादी वजह की उन्होंने पूरी उपेक्षा कर दी अगर समस्या की जड़ों में और भी गहरे झांका जाए, तो प्रमुख कारण के तौर पर संसाधनों- खासकर जमीन से जुड़ी सुरक्षा का पहलू स्पष्ट नजर आता है। जहां तक आइडेंटी पार्सिलिंग्स की बात है, तो उसमें दोनों समुदाय शामिल रहे हैं। हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ-साथ चर्चा ने भी इस होड़ को बढ़ाने में भूमिका निर्भाई है। किसी निष्पक्ष सरकार का दायित्व इन विभाजन रेखाओं और उनसे जुड़ी आशंकाओं को दूर करना होता। मगर जब सरकार खुद एक पक्ष बन जाए, तो समस्या का निकलना और दूर हो जाता है। इसीलिए अपसपा से भी ज्यादा उम्मीद नहीं बंधी है।

विपक्ष के तो वादे भी छोटे हैं

सोचें, नरेंद्र मोदी ने कहां से शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर 2014 में मैदान में उतरे तब काले धन का जुमला बोला था और कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वापस आ जाए तो हर भारीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। इसके जवाब में विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं कि जीते तो खातों में दो-दो हजार या तीन-तीन हजार रुपए डालेंगे। सोचें, कहां 15 लाख और कहां तीन हजार रु! दे तो मोदी भी दो- तीन हजार ही रुपए दे रहे हैं लेकिन उन्होंने वादा 15 लाख रु का किया था। यहां विपक्षी वादा ही दो-तीन हजार रुपए का कर रहा है। अदानी-अंबानी से लेकर 25-50 लाख रु का क्यों नहीं कर रहा? मोदी ने किसानों को दी है छह हजार रुपए की सालाना रेवड़ी लेकिन कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इसके जवाब में विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं? किसानों के लिए उनका क्या वादा है? सिर्फ इतना कि कर्ज माफ कर देंगे। क्या इससे काम चलेगा? किसानों की आय कम से कम चार गुनी कर देना का वादा करना चाहिए। प्रधानमंत्री बनते ही 2014 के दो अक्टूबर को मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और थोड़े दिन के अभियान के बाद घोषित कर दिया कि देश स्वच्छ हो गया और खुले में शौच से मुक्त हो गया। यहां अलग बात है कि राजधानी दिल्ली में अहले सुबह बाहर निकल जाइए तो हजारों लोग बोतल में पानी लेकर शौच के लिए जाते दिख जाएंगे। मोदी के स्वच्छता के जवाब में विपक्ष के पास क्या एंडेंडा है? मोदी ने हर घर शौचालय देने की बता कही थी तो 'इंडिया' के नेताओं को हर घर में टाइल्स वाले और गोजर लगे बाथरूम देने का वादा करना चाहिए, जिसमें 24 घंटे पानी की सप्लाई हो। बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री को बुला कर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान मोदी ने शुरू किया। लोगों से बेटियों के साथ सेलफी डालने की अपील की गई। लेकिन हकीकत क्या है? महाकाल की नगरी उन्जैन में 12 साल की खून से लथपथ बेटी आठ किलोमीटर तक चलती रही और एक आदमी मदद के लिए सामने नहीं आया। बलात्कार का शिकार हुई नाबालिग बेटी को मंदिर के एक पुजारी राहत शर्मा से मदद मिली।

मेडिकल पढ़ाई की गुणवत्ता क्या रह गई ?

अजीत द्विवेदी

हालांकि अपनी सुविधा के लिए इसे कोरोना महामारी से जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि महामारी के स्कूल-कॉलेज बंद हो गए थे और पठन-पाठन का वैकल्पिक यानी ऑनलाइन सिस्टम अपनाया गया था, जिससे लर्निंग प्रोसेस पर व्यापक असर हुआ। लेकिन यह अकेला कारण नहीं है, बल्कि कई कारणों में से एक कारण है। बहरहाल, शिक्षा के स्तर में गिरावट का एक बड़ा नमूना अभी देखने को मिला है, जब नेशनल मेडिकल कॉंसिल यानी एनएमसी ने मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी विशेषज्ञता वाली चिकित्सा शिक्षा के लिए दाखिले का कटऑफ मार्क्स शून्य कर दिया। यानी एमबीबीएस पास करने वाले जो डॉक्टर इससे आगे की उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और किसी खास विषय का विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उनको अगर नीट की पीजी परीक्षा में शून्य अंक आया है तब भी वे पीजी में दाखिला ले सकेंगे। इतना ही नहीं 13 छात्र ऐसे हैं, जिनको शून्य से भी कम अंक मिले हैं। उनके मार्क्स निर्गोटिव में हैं फिर भी वे विशेषज्ञ बनने की पढ़ाई के लिए पीजी कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। सोचें, यह कैसी हैरान करने वाली और कितनी दुखद बात है! शून्य या माइनस मार्क्स वाले जिन छात्रों को पीसी कोर्स में दाखिला दिया जाना है वे ऐसे छात्र हैं, जिन्होंने चार या पांच साल तक मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल का कोर्स पूरा करने के बाद उनका स्तर यह है कि वे पीजी कोर्स में दाखिले की परीक्षा में एक भी अंक हासिल नहीं कर पाए तो फिर उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई का क्या मतलब है? नीटी पीजी की परीक्षा में शून्य या माइनस मार्क्स हासिल करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दाखिला देने की



बजाय इस बात को जांच को जाना चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों ने किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। उस मेडिकल कॉलेज की पूरी फैकल्टी की जांच की जानी चाहिए और उसका पंजीयन रद्द किया जाना चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है कि चार-पांच साल तक एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने वाले लोग पीजी कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में एक भी अंक नहीं हासिल कर पाएं। ऐसे डॉक्टर किस तरह से लोगों का इलाज करेंगे? क्या उनको डॉक्टर बनाना आम लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं है? यह सही है कि देश में आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है लेकिन क्या इसके लिए नीम हकीम डॉक्टर बना कर बाजार में उतार दिया जाएगा? क्या एनएमसी ने नीम हकीम खतरा ए जान का मुहावरा नहीं सुना है? मेडिकल में दाखिले के लिए पहले से चल रही तमाम प्रवेश परीक्षाओं या प्रक्रिया को खत्म करके 2017 में नीट को अपनाया गया था।

उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि पीजी कोर्स में दाखिले के लिए कटऑफ जीरो या माइनस में किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की 13 हजार से ज्यादा सीटें खाली रह जातीं देश में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी अलग अलग क्षेत्र का विशेषज्ञता की पढ़ाई के लिए कुल 68 हजार सीटें हैं इन 68 हजार सीटों पर दाखिले के लिए एमबीबीएस कर चुके करीब सवा दो लाख डॉक्टरों ने परीक्षा दर्ती। इनमें से सिर्फ 55 हजार डॉक्टर पीजी कोर्स में दाखिले के लिए तय किया गया कटऑफ मार्क्स हासिल कर सके। बाकी करीब पौने दो लाख डॉक्टरों के बारे में सोचें, जो दाखिला परीक्षा का कटऑफ मार्क्स नहीं हासिल कर सके! इस बार खाली रह गए सीटों को भरने के लिए उन सबको छूट दे दी गई है कि वे कार्डिसिलिंग में शामिल हों। अब इससे जुड़े दूसरे पहलू को देखें। चूंकि नेशनल मेडिकल कॉर्सिल ने नीति पीजी की परीक्षा में शामिल हुए सभी एमबीबीएस

पाकिस्तान से बातचीत का सवाल....

કુલદાપ ચદ આંનહાત્રા

पिछली बार बातचीत करने के लिए नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भेजा था, इस बार उन्हीं के पुत्र और पौत्र फ़रूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भेजा जा सकता है। इतना ही बातचीत का एजेंडा उन्हें स्पष्ट रहना चाहिए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 1964 में जम्मू-कश्मीर के मुदे पर पाकिस्तान से गोलमेज कान्फ्रेंस करने के लिए पाकिस्तान भेजा था। इसकी चर्चा यथास्थान की जाएगी। अब श्रीनगर की जामिया मस्जिद के मीरवाइज सैयद उमर फ़रूख ने आग्रह किया है कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बातचीत कर लेनी चाहिए। वे कामी लम्बे अरसे बाद 22 सितम्बर 2023 को मस्जिद में आए थे। वे इस मस्जिद से अपने भक्तों को प्रायः सम्बोधित करते रहते हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। मीर का अर्थ मुख्य होता है जिसे अंग्रेजी में चीफ़ भी कह सकते हैं। वाइज का अर्थ प्रचारक है। लेकिन यहां प्रचारक का अर्थ इस्लाम का प्रचारक है। मीरवाइज यानी इस्लाम का मुख्य प्रचारक। मीरवाइज मस्जिद में मुसलमान बच्चों को मजहब की शिक्षा भी देते हैं। लेकिन पिछले आठ नौ दशकों में उन्होंने कश्मीर की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। 1931 में मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना में भी एक मीरवाइज का ही हाथ था। श्रीनगर में दो मीरवाइज हैं। एक तो जामिया मस्जिद के मीरवाइज हैं और दूसरे खानगाहे मौला के मीरवाइज हैं। उन्हें मीरवाइज हमदानी भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों मीरवाइजों के पूर्वज सैयद अली हमदानी हैं। हमदानी ईरान में तैमूरलंग के सताए हुए थे। उसी के डर से वे भागकर कश्मीर आ गए थे। लेकिन अब सैयद अली हमदानी की संतानें दो भागों

में बट चुकी है। एक जामिया मस्जिद में मीरवाइज है और दूसरा खानगाहे मौला में मीरवाइज है। इतना लम्बा कालखंड गुजर जाने के कारण, अब ये परस्पर विरोधी ही नहीं हैं, बल्कि कई बार इनके भक्त आपस में मारपीट भी करते हैं। ये दोनों मीरवाइज मुसलमानों की अशरफएटीएम श्रेणी से आते हैं। मुसलमानों की अशरफया एटीएम श्रेणी में अरब, तुर्क व मुगल मंगोल मूल के मुसलमान आते हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे स्व. बशीर अहमद डाबला इन्हें मुस्लिम्ज ऑफ़ फरेन ओरिजिन कहते हैं। कश्मीर में मुसलमानों का दूसरा बहुत बड़ा समूह डीएम या देसी मुसलमानों का है। ये स्थानीय लोग हैं जो पिछले छह सौ सालों में किन्हीं भी कारणों से अपनी विरासत छोड़ कर इस्लाम पंथ में चले गए थे। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने यह बात कही थी। आजाद देसी मुसलमानों की जमात से तालुक रखते हैं। अशरफ मुसलमान देसी मुसलमानों को अलजाफपसमांदा, अरजाल न जाने क्या क्या कहते हैं। कश्मीर घाटी में मीरवाइजों को एटीएम/अशरफ मूल के मुसलमानों का नेता भी माना जाता है। एटीएम और डीएम में प्रायः झगड़ा भी होता रहता है। कई बार तो झगड़ा जरूरत से ज्यादा भी बढ़ जाता है। कई दशक पहले झगड़ा उतना बढ़ गया था कि कश्मीर के देसी मुसलमानों ने स्वयं को शेर और मीरवाइज के अशरफ मुसलमानों को बकरा कहना शुरू कर दिया था। परोक्ष रूप से शेर-बकरा का यह झगड़ा किसी न किसी रूप में आज तक चला हुआ है। 1947 में जामिया मस्जिद के मीरवाइज मोहम्मद यूसुफशाह भाग कर पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें तथाकथित आजाद कश्मीर का राज्यपाल भी बनाए रखा। उस वक्त कश्मीर के देसी

मुसलमानों ने आवाज भी उठाई थी कि अब मोरवाइज़ का पद किसी देसी मुसलमान को मिलना चाहिए लेकिन यह पद आज तक परम्परागत ही चला आ रहा है। वर्तमान मोरवाइज़ सैयद उमर फ़रूक के पिता को आतंकवादियों ने गोली से उड़ा दिया था। वे वैसे तो आतंकवादियों की बोली ही बोलते थे, लेकिन बीच में उन्होंने पाकिस्तान द्वारा निर्धारित रास्ते से एक दो कदम अलग से चलने की कोशिश की थी, जिसके खिमियाज़ उन्हें भुगतान पड़ा। उमर फ़रूक लम्बे अन्तराल के बाद 22 सितम्बर 2023 को जामा मस्जिद में अपने श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे थे। रिकार्ड के लिए वे अभी भी तथाकथित हुर्रियत कान्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं वहां उन्होंने कशमीर की आजकल की राजनीति को लेकर भी सुझाव दिए। उनका मानना था कि कशमीर हिन्दू वापस कशमीर में आ सकें, इसके लिए माहौल बनाना चाहिए। उनका कहना था कि कशमीर को लेकर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ऐसा सुझाव पिछले दिनों फ़रूक अब्दुल्ला और उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला भी दे चुके हैं। यहां तक कि पीड़ीपी की अध्यक्षा सैयद महबूबा मुफ्ती भी यही बात कह चुकी हैं। इन लोगों का यह सुझाव सचमुच काम का है और ये लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। जम्मू कशमीर व लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने बलपूर्वक अपने कब्जे में रखा हुआ है। उसको लेकर पाकिस्तान से तीन लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद जम्मू कशमीर व लद्दाख का वह हिस्सा मुक्त नहीं करवाया जा सका। सभी मानते हैं कि लड़ाई की बजाय शान्ति से मसलें का हल होना चाहिए। यदि पाकिस्तान बलपूर्वक कब्जा ए गए। हिस्से शान्तिपूर्ण तरीके से छोड़ देतो मसले का इससे बेहतर क्या हल हो सकत है? लड़ाई के मैदान में जाने की बजाय मेज पर बैठें।

प्रशिक्षक को सही प्रबंधन दो....

भूपिंदर सिंह

क्या हिमाचल सरकार पंजाब, गुजरात आदि राज्यों की तरह उत्कृष्ट खेल परिणाम दिलाने वाले बढ़िया प्रशिक्षकों को यहां लगातार कई वर्षों के लिए अनुबंधित कर प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य में ही प्रशिक्षण सुविधा दिला कर पलायन रोक नहीं सकती है ? इससे प्रदेश में खेल वातावरण बनेगा तो हर खेल प्रशिक्षक चाहेगा कि उसके शिष्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करें आज का अभिभावक खेलों में भी अपने बच्चों का कैरियर देख रहा है, क्योंकि खेल आज अपने आप में एक प्रोफेशन है। मानव द्वारा विज्ञान में बहुत प्रगति कर प्रौद्योगिकी व चिकित्सा के क्षेत्र में नए-नए सफल शोध कर जीवनशैली को काफ़ी आसान व सुविधाजनक बना लिया है, मगर शिक्षण व प्रशिक्षण में शिक्षक व प्रशिक्षक की भूमिका का महत्व आज भी वही है जैसा हजारों साल पहले था। महाभारत में कृष्ण सारथी नहीं होते तो क्या अर्जुन भीष्म, कर्ण व अन्य अजेय महारथियों को हरा पाते। विश्व स्तर पर किसी खेल विशेष में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्षमतावान प्रशिक्षक का होना बेहद जरूरी होता है। हमारे यहां खेल प्रशिक्षण के लिए वह वातावरण ही नहीं बन पाया है, जिसमें प्रशिक्षक खिलाड़ी से राशीय व अंतरराशीय स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम दिला सके। खेल प्रशिक्षण दस साल से भी अधिक समय तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इतनी समय अवधि खेल प्रशिक्षण को देकर ही खिलाड़ी अपने प्रदेश व देश को गौरव दिला पाता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं बन पाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रशिक्षकों को कभी विभिन्न विभागों की भर्तियों में डूटी तो कभी मेलों व उत्सवों में हाजिरी भरनी पड़ती है। खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति ही उच्च खेल परिणामों के लिए को गई होती है, मगर यहां पर प्रशिक्षकों को केवल मल्टीपर्पज कर्मचारी बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश



के अधिकतर प्रशिक्षकों का कार्य उच्च खेल प्रशिक्षण से हट कर अपनी फिटनेस तथा सेना में भर्ती कराने तक सीमित हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मेलों व उत्सवों में किसी और खेल का प्रशिक्षक किसी और ही खेल की प्ले फैल्ड में नजर आता है। इसी तरह पुलिस आदि विभागों की भर्तीयों में एथलेटिक्स प्रशिक्षकों की दूर्योगी तो समझ आती है, मगर वहां तो हर खेल के प्रशिक्षक को भेज दिया जाता है। नियमानुसार इन भर्तीयों के लिए एथलेटिक्स प्रशिक्षक ही सक्षम है, क्योंकि इस टैस्ट में केवल एथलेटिक स्पर्धाओं को ही रखा गया है। ऐसे में एथलेटिक्स प्रशिक्षक की दूर्योगी तो समझ आती है, मगर वहां अन्य खेलों, जैसे कुर्ती, मुक़बाजी, हैंडबाल व वॉलीबाल आदि के प्रशिक्षक का क्या औचित्य है, इस बात का उत्तर किसी के भी पास नहीं है। विभिन्न सरकारों ने खेल ढांचे में काफ़ी तरकी भी की है, मगर क्षमतावान प्रशिक्षकों की नियुक्ति के बारे में हिमाचल में अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। स्तरीय प्रशिक्षकों के बिना उत्कृष्ट प्रदर्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो प्रशिक्षक खेल प्रशिक्षण से दूर रह कर मौज-मस्ती कर रहा है, वह तो खुश रहता होगा, मगर

जो सच ही में प्रशिक्षण करवा रहा होगा, वह जब कदिनों तक खेल मैदान से दूर रहेगा तो पिछकौन अधिभावक अपने बच्चे को बिना प्रशिक्षक के मैदान में भेजेगा। हृदय तो तब हो जाती है जब राज्य में चल रहा खेल छात्रावासों में नियुक्त प्रशिक्षकों की ड्यूटी भर्तियाँ में लगा दी जाती हैं और खेल छात्रावास में रह रहे खिलाड़ियों को भी खेल प्रशिक्षण से दूर कर दिया जाता रहा है। क्या प्रतिभा खोज से चयनित इन अधिभावक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षक से कृष्ण समय वेलिए ही सही, इस तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम से दूर करने कहाँ तक उचित है? खेल छात्रावासों में नियुक्त प्रशिक्षकों की ड्यूटी खेल प्रशिक्षण के सिवा और कहाँ भी नहीं होनी चाहिए। आजकल हर शिक्षित मां-बाप वे दो और कई जगह तो एक ही बच्चा है, ऐसे में वह उस उस क्षेत्र में उच्चतम शिखर तक ले जाना चाहता है जिसमें बच्चे की रुचि व उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रतिभावी हो। आज का अधिभावक अपने बच्चों के कैरियर की खातिर ही सरकार की मुफ्त शिक्षा सुविधाओं को छोड़कर निजी क्षेत्र की महंगी, मगर अधिक गुणवत्तवाली शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है।

आज लाखों प्रतिभाशाली विद्यार्थी निजी कोचिंग संस्थानों में डाक्टर व इंजीनियर बनने इसलिए जमा दो की परीक्षा से कई वर्ष पहले पहुंच रहे हैं। इसी तरह अब खेल क्षेत्र में भी हो रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के लिए खेलों में भी कैरियर तलाश रहा है और इस सबके लिए अच्छी खेल सुविधाओं के साथ-साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षक भी लगातार कई वर्षों तक उसके बच्चों को मिलना चाहिए ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता बनने का सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। इसलिए देश में निजी खेल अकादमियों के चलन भी बढ़ रहा है। गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी के विश्व स्तर के परिणाम सबके सामने हैं। यह सब लगातार अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम का ही नतीजा है। इस समय विभिन्न खेलों के लिए देश में निजी स्तर पर कई आकादमियां शुरू हो चुकी हैं। इन खेल अकादमियों को अधिकतर पूर्व ओलंपियन चला रहे हैं और यहां से अच्छे खेल परिणाम भी मिल रहे हैं। इन अकादमियों में जो विशेष है, वह यह है कि यहां उच्च क्षमता वाला प्रशिक्षक लगातार उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के पास आज विभिन्न खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड तैयार हैं, वहां पर या तो प्रशिक्षक हैं ही नहीं और जहां हैं भी, वे या तो प्रशिक्षण से बेरुख हैं। या उनमें अच्छे स्तर के खेल परिणाम दिलाने की क्षमता ही नहीं है। क्या हिमाचल सरकार पंजाब, गुजरात आदि राज्यों की तरह उत्कृष्ट खेल परिणाम दिलाने वाले बढ़िया प्रशिक्षकों को यहां लगातार कई वर्षों के लिए अनुबंधित कर प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य में ही प्रशिक्षण सुविधा दिला कर खेल प्रतिभा का पलायन रोक नहीं सकती है? इससे प्रदेश में खेल वातावरण बनेगा तो हर खेल प्रशिक्षक प्रेरित होकर चाहेगा कि उसके शिष्य भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इस सबके लिए खेल विभाग व जहां प्रशिक्षक प्रशिक्षण करवा रहा है, वहां उसे सही प्रबंधन देकर प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना होगा। तभी पहाड़ की संतानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के सही मौके मिलेंगे।

